डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 जून, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2025

| वर्ष 69 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित

विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका-महासम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 में सहकार से समृद्धि और विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका के सूत्र को देश के सामने रखा गया

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सभी लोगों को जागरूक कर, पारदर्शिता के नए आयाम तय कर सहकारी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता

सहकारिता क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लाभ जब तक PACS और किसानों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान साइंस ऑफ कोऑपरेशन और साइंस इन कोऑपरेशन पर बल दिया है

देशभर में Cooperation Amongst Cooperatives को प्राथमिक स्तर पर अपनाने की जरुरत, जिससे सहकारी संस्थाओं का पूरा कामकाज सहकारी संस्थाओं के साथ ही हो

मोदी सरकार 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना करेगी

जल्द ही लिक्विडेशन में गई PACS के निपटारे और नए पैक्स के लिए भी नीति आएगी

अहमदाबाद, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा "विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका" पर आयोजित महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता शब्द पूरे विश्व में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वर्ष 1900 में था। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 2021 से सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास शुरू हुआ और इसीलिए सहकारिता वर्ष की शुरुआत भारत में करने का निर्णय लिया गया।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई शुरूआत के तहत सहकार से समृद्धि और विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका के दो सूत्रों को देश के सामने रखा गया। उसी शुरूआत के अंतर्गत गुजरात में इस सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लाभ जब तक निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) और किसानों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाएं। हमें सभी प्रकारकी सहकारी संस्थाओं में जागरूकता, प्रशिक्षण और पारदर्शिता लाने का प्रयास करना होगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान साइंस ऑफ कोऑपरेशन और साइंस इन कोऑपरेशन पर भारत सरकार ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के समय देश में शुरू हुआ सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे देश के एक बड़े भाग में लगभग समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन के तहत हर राज्य और जिले तक सहकारिता का विस्तार हो। साथ ही हर राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थिति सुधरे, जिलास्तरीय संस्थाएं मजबूत हो और उनके माध्यम से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर का सहकारी ढांचा भी मजबूत बने। श्री शाह ने कहा कि कई वर्षों से चली आ रही वैश्विक त्रि-स्तरीय सहकारिता ढांचे की कल्पना में हमने चौथे स्तर को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के ढांचे की हर सहकारी गतिविधि से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों, राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाओं, जिलास्तरीय संस्थाओं और हर क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करते हुए पूरे देश में सहकारिता को पहुंचाना ज़रूरी है। श्री शाह ने कहा कि इसके लिए हमें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उपयोग करना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह पूरा अभियान तीन स्तंभों पर आधारित है - सहकारिता को शासन के मुख्य प्रवाह का हिस्सा बनाना, सहकारिता आंदोलन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता और प्रमाणिकता लाना और अधिक से अधिक नागरिकों को सहकारिता आंदोलन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को गति देना। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्तंभों के आधार पर सहकारिता वर्ष के दौरान कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए अनेक प्रकार के लगभग 57 इनीशिएटिव अब तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमें गुजरात सहित पूरे देश में Cooperation Amongst Cooperatives के प्रयोग को प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए जिससे सभी सहकारी संस्थाओं का पूरा कामकाज सहकारी संस्थाओं के साथ ही हो। सभी प्राथमिक सहकारी समितियों, डेयरी आदि का बैंक अकाउंट ज़िला सहकारी बैंक में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सभी सहकारी संस्थाओ के बीच सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रयास को गति देनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि दश के हर राज्य में सहकारिता से जुड़े सभी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हम PACS को मजबूत नहीं करते तब तक सहकारी ढांचा मजबूत नहीं हो सकता है, इसीलिए मोदी सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का निर्णय लिया है। इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न प्रकार की लगभग 22 गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए भी नीति ले कर आने वाली है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में अनेक प्रकार की नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सभी लोगों को जागरूक कर, पारदर्शिता के नए आयाम तय कर और भर्तियां कर हमें सहकारी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाने और सहकारी नेटवर्क को सशक्त बनाने पर बल दिया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्क्युलैरिटी विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 'श्वेत क्रांति 2.0' के तहत सहकारी डेयरी क्षेत्र में सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सहकारी डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया

पहली समिति- 'पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान', दूसरी समिति- 'गोबर प्रबंधन मॉडल विकसित करने' और तीसरी समिति- 'मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्क्युलर उपयोग' को बढ़ावा देगी

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्क्युलैरिटी विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी, डेयरी और पशुपालन विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अध्यक्ष डॉ मीनेश शाह और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी केवी भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए बैठक में सहकारी डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान पर काम करेगी, दूसरी गोबर प्रबंधन के मॉडल विकसित करेगी, और तीसरी मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्क्युलर उपयोग को बढ़ावा देगी।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब हम श्वेत क्रांति 2.0 की ओर अग्रसर है, तो हमारा लक्ष्य केवल डेयरी सहकारिता का विस्तार करना और उन्हें दक्ष एवं प्रभावी बनाना ही नहीं होना चाहिए बल्कि डेयरी के एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो सतत हो और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हो। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो हमें एकीकृत सहकारिता के नेटवर्क का सृजन करना होगा जहां अधिकांश कार्य पारस्परिक सहयोग और सहकारिताओं के बीच में ही हो।

श्री अमित शाह ने इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुँचाया जाए। साथ ही उन्होंने दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा डेयरी संयंत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ये सभी प्रयास न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि डेयरी क्षेत्र को अधिक सतत एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है और सहकारी डेयरी क्षेत्र इसका एक उत्तम उदाहरण है, जो हमारे लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डेयरी सहकारी समितियाँ भारतीय दुग्ध क्षेत्र में दूध उत्पादन और विपणन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये समितियाँ छोटे किसानों को स्थिर बाजार, ऋण सुविधा, पशु चिकित्सा और प्रजनन जैसी सेवाएं प्रदान कर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त भी बना रही हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमें मिलकर 'सस्टेनेबिलिटी से सर्क्युलैरिटी' तक का सफर तय करना है जो बहुआयामी होगा और जो कार्य आज निजी क्षेत्र कर रहे है वे कार्य किसानों की अपनी सहकारी संस्था करेगी। इसमें तकनीकी सेवाएँ, पशु आहार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु रोग नियंत्रण, गोबर प्रबंधन तथा डेयरी और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में संकलन से लेकर प्रोसेसिंग तक की गतिविधियां शामिल हैं।

सहकारिता मंत्री ने अमूल जैसे सफल सहकारी मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि "सहकार से समृद्धि" का विज़न आज साकार हो रहा है और इसमें "सहकारिता में सहकार" एक अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर न केवल डेयरी क्षेत्र में इस सफलता को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों को अन्य गतिविधियों से भी जोड़कर उन्हें विस्तारित और मजबूत कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि ये सभी प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी के विकसित भारत के लक्ष्य को समेकित रूप से हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी हितधारकों को एक साथ लाया है जिससे अब नीति निर्माण, वित्त पोषण से लेकर ग्राम स्तरीय सहकारिता के गठन और उन्हें बहुउद्देशीय बनाने का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। एनडीडीबी ने सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और उनके द्वारा विकसित बायोगैस और गोबर प्रबंधन कार्यक्रम आज पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे और आगे ले जाने की जरूरत है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सहकारिता के उन्नयन के लिए कार्य कर रही राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नाबार्ड इत्यादि की सराहना की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में इनके परस्परिक सहयोग से निश्चित रूप से सहकारिता को बल मिलेगा और किसान केन्द्रित योजनाओं को पूरे भारत वर्ष में लागू किया जा सकेगा।

कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है प्रदेश : मंत्री श्री कुशवाह

उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, प्रदेश में कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है राज्य शासन का प्रयास कृषि के साथ उद्यानकी के क्षेत्र में नवीन उन्नत तकनीकी अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्पादित माल की मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का कार्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार में अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है किसानों को उनके

उत्पादन का बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए क्रेता विक्रेता सेलर्स मीट का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानकी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है प्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बन गया है राज्य सरकार का प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मध्यप्रदेश में स्थापना करके उत्पादित माल की बेहतर कीमत किसानों को प्राप्त हो सके। उन्होंने कृषि उद्योग समागम को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे।

उपराष्ट्रपति ने किया 'कृषि-उद्योग समागम 2025' का शुभारंभ

मध्यप्रदेश मॉडल पूरे देश में लागू हो - उपराष्ट्रपति श्री धनखड़

कृषि को उद्योग से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल, किसानों को मिलेगा व्यापक लाभ

"कृषि विकास से बनेगा समृद्ध भारत, मप्र मॉडल अपनाएं सभी राज्य" - उपराष्ट्रपति श्री धनखड़

नरसिंहपुर में भव्य शुभारंभ हुआ 'कृषि-उद्योग समागम 2025' का, कृषि-आधारित उद्योगों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

नरसिंहपुर, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का रास्ता अब खेतों और गांवों से होकर निकलेगा – यह विश्वास प्रकट करते हुए भारत के उपराष्ट्रपतिश्री जगदीप धनखड़ने कहा कि खेती-किसानी केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित न रहे, बल्कि इसे उद्योग और नवाचार से जोड़कर किसानों को उद्यमी बनाना समय की मांग है।वेनरसिंहपुर जिला मुख्यालय में आयोजित 'कृषि-उद्योग समागम 2025'के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उनके साथराज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवभी मंच पर उपस्थित रहे।

'कृषि-उद्योग समागम 2025' का हुआ शुभारंभ

तीन दिवसीय (26 से 28 मई तक) चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन, कन्या पूजन और भगवान बलराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करकी गई। इस अवसर परडॉ. (श्रीमती) सुदेश धनखड़भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा किकिसानों की समृद्धि से ही देश की समृद्धि संभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस अभिनव पहल को देशभर में अनुकरणीय बताते हुए अन्य राज्यों को भी मध्यप्रदेश मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल को सराहा गया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा कृषि को उद्योग से जोड़ने की इस पहल को 'ग्राम से ग्लोबल' की दिशा में एक बड़ी शुरुआत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक मेला नहीं, बल्किप्रसंस्करण, विपणन, तकनीक और निवेशको जोड़ने वाला एक मंच है।

मुख्य बातें मुख्यमंत्री के संबोधन से:

- नरसिंहपुर को दाल का कटोरा कहा, जहां की तुअर दाल को मिलाGI टैग।
- प्रदेश के किसानों को 2600 रु./ क्विंटल की दर से गेहूं खरीद कर दी गई राहत।
- 32 लाख सोलर पंपों की योजना में किसानों को 90% अनुदान।
- 1300 करोड़ रुपए के कृषि उद्योग, जिनसे 22 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे।
- डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजनासे दुग्ध उत्पादन को मिलेगा नया बल।
- GIS:2025 में 30 लाख करोड़के निवेश प्रस्ताव।

प्रदेश में कृषि आधारित फूड पार्क का निर्माण

मुख्यमंत्री ने बताया किकृषि आधारित उद्योगोंको आगे बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं:

1. नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में फूड प्रोसेसिंग हब
2. छिंदवाड़ा (बोरगांव) में 40 इकाइयों का फूड पार्क
3. मंडला (मनेरी) में भी 40 इकाइयों वाला उद्योग क्षेत्र

'विकसित भारत@2047' का आधार – किसान

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा किदेश की 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। 346,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि "किसान केवल उत्पादक नहीं, अब उद्यमी भी बनें।"

उन्होंने यह भी कहा कि देश में 720 कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अन्य संस्थाएं मिलकर खेत से फैक्ट्री तक तकनीक पहुंचाने में मदद कर रही हैं।

राज्यपाल ने की नरसिंहपुर की महत्ता पर चर्चा

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेलने नरसिंहपुर कोआध्यात्मिक केंद्रबताया औरमकर संक्रांति मेलेकी परंपरा को याद किया। उन्होंने कहा किकृषि मेलों से किसानों को आधुनिक जानकारी और संसाधनों का लाभ मिल रहा है।

राज्य स्तरीय कृषि उद्योग समागम – अक्टूबर में सीहोर में

मुख्यमंत्री ने बताया कि:

- पहला कृषि मेला सीतामऊ (मंदसौर) में
- दूसरा (वर्तमान) नरसिंहपुरमें
- तीसरा सतना में जुलाई में
- चौथा मुरैना (चंबल) में
- राज्य स्तरीय समागम 12-14 अक्टूबर को सीहोर में होगा।

प्रदर्शनी और विकास कार्यों का लोकार्पण

उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने नई कृषि तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और116 करोड़ रुपए के 86 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन भी किया गया।

साथ ही जैविक खेती कर रहे नवाचारी किसानों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

अन्य प्रमुख उपस्थिति

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे –

- श्री प्रह्लाद पटेल (पंचायत मंत्री)
- श्री उदय प्रताप सिंह (शिक्षा व परिवहन मंत्री)
- श्री गोविंद सिंह राजपूत (खाद्य व आपूर्ति मंत्री)
- श्री एदल सिंह कंषाना (कृषि मंत्री)
- श्री नारायण सिंह कुशवाहा (उद्यानिकी मंत्री)
- सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया
- विधायक श्री विश्वनाथ सिंह सहित हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीणजन।

'कृषि-उद्योग समागम 2025' के माध्यम से मध्यप्रदेश ने न केवल कृषि की दशा और दिशा बदलने की मुहिम छेड़ी है, बल्कि देश को यह संदेश दिया है किखेती और उद्योग का संयोग ही आत्मनिर्भर भारत की असली नींव है।

यूं ही नही बनी रानी से मां और फिर देवी अहिल्या बाई होल्कर

भोपाल, आसान नही होता सत्ता के कठोर अपरिहार्य चलन को ढकेल कर, ममता को बरकरार रखते हुए सामाजिक रुढियों को तोड पाना। बात जब सदियों के काबिज धर्म और पारिवारिवारिक रस्मों और दौर को बदलने की हो तो अच्छे से अच्छे रणनीतिकार, राजनितज्ञ भी विरोध के डर से हिम्मत नही जुटा पाते है। इस रानी की न्याय प्रियता, शासन संचालन और धार्मिक कार्यों घाटों के निर्माण पर बहुत कछ लिखा गया। लेकिन हम बात करके देवी अहिल्या के नारी उत्थान की दिशा ने किए गए दूरदर्शी कार्यों की।

लेकिन होल्कर घराने की बहु रानी अहिल्या बाई होल्कर - महिला सेना का गठन करने वाली उस दौर की वे शायद प्रथम ही शासक थी। इतना ही नही युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक रुप से सक्षम बनाने की पहल उन्होंने ही की। देश में पहली बार विधवा पेंशन की शुरुआत हुई। यही वजह है कि उनकी आयु भले ही 70 वर्ष रही हो लेकिन कई पीढियों को, दशकों तक चार सदी बीत जाने के बावजूद भी रानी अहिल्या आज भी प्रासंगिक है।

इतना ही नही, पाखंडी धर्मवेताओं के विरोध को अकाट्य तर्कों, संयम तो कभी कडक निर्णय ले चुनौति देने से भी नही चुकी रानी अहिल्या। और इस तरह समाज के बडे वर्ग को महिला शिक्षा का अधिकार दिलवाया । कानून को पालन करवाने में महज कडक रुख नही अपनाया वरन ऐसे मानवीयता को प्राथिमकता देते हुए नए कानूनों की ईबारत लिखी। जो आज भी अनुकरणीय है। मसलन, विधवा संपति जप्त होने के कानून को समाप्त किया, विधवा पेंशन लागू की, सती प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं के रोजगार की चिंता कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया।

उनके द्वारा स्थापित माहेश्वरी साड़ी का उद्योग आज भी कई परिवारों की रोजी रोटी है। खासकर महिलाएं इसे बखूबी चला रही है। जहां तक बात है पेंशन की तो उस समय यह कानून था कि, अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र न हो, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपनी पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। महिलाओं के उत्थान के लिए और लड़कियों को अच्छी शिक्षा के साथ रोजगार मिले इसके लिए भी काफी कार्य किए। महाराष्ट्र के चौंडी (वर्तमान में हमदनगर जिले) गांव के एक साधारण परिवार में अहिल्या का में हुआ था। इस छोटी सी बालिका ने बडे बडे योद्धाओं को धूल चटाई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का गेहूँ के रिकार्ड उपार्जन पर खाद्य मंत्री ने किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि की घोषणा का परिणाम - 77.75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित - खाद्य मंत्री श्री राजपूत

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के परिणामस्वरूप रबी विपणन वर्ष 2025-26 में लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख 75 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गत वर्ष 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ था। इंदौर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उन्होंने किसानों के हित में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिये गये बोनस एवं उसके बाद हुए रिकार्ड गेहूँ उपार्जन पर उनका अभिनंदन कर लोकहित में कार्य करने के लिए लोकमाता की प्रतिमा भेंट की। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि गेहूँ के उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

एक लाख से अधिक महिला किसानों से 8.98 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। इस तरह से गेहूँ का उपार्जन 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि 9 लाख किसानों में से 1 लाख 23 हजार महिला किसानों द्वारा 8 लाख 98 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 3623 केन्द्र खोले गए जिसमें से 293 केन्द्र महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किए गए, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। महिला किसानों के खाते में 2 हजार 335 करोड़ रूपये का बोनस सहित भुगतान किया जा चुका है। किसानों के खातों में कुल 19 हजार 322 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए समिति स्तरीय 3 हजार 176 पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त 9311 एमपी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्रों, पंचायतों के केन्द्रों के साथ किसान द्वारा स्वयं पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के व्यय को सीमित करने के लिए 2440 केन्द्र गोदाम स्तरीय बनाए गए जिससे परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय की बचत हुई है।

किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्था

समर्थन मूल्य का लाभ बिचौलियों/व्यापारियों द्वारा समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करने से रोकने हेतु इस वर्ष बायोमेट्रिक / ओटीपी आधारित किसान पंजीयन की व्यवस्था की गई। किसानों द्वारा विक्रय उपज के समर्थन मूल्य की राशि उनके बैंक खाते में निर्बाध रूप से भुगतान किया जा सके, इसलिए कृषक के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था की गई है। कृषक द्वारा स्वयं उपार्जन केन्द्र का चयन कर उपज विक्रय के लिये स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गई। उपार्जन करने वाली समितियों को दैनिक व्यय की पूर्ति हेतु मंडी लेबर व्यय का भुगतान प्रतिदिन किसानों के भुगतान के साथ करने की व्यवस्था की गई है। शनिवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में किसान द्वारा अपनी उपज विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र पर लाने पर खरीदी की गई। इस वर्ष पंजीयन 20 जनवरी 2025 से शुरू कर दिया गया जो 9 अप्रैल तक चलता रहा। इस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में पंजीयन के लिए ज्यादा समय दिया गया था।

इस दौरान मंत्रि-परिषद के सदस्य, अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा और एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा भी उपस्थित थे।

सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियाँ

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग में नित नये नवाचार किये जा रहे हैं और नवाचार से गति पकड़ता जा रहा है मध्यप्रदेश सहकारी आंदोलन गतिमान हुआ है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भोपाल के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में बताया कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा। उन्होंने शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिये प्रदेश की सराहना की।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिये लगभग हर माह सहकारिता संबंधी आयोजन करने का संकल्प लेकर काम किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवायी जा रही है। नवाचार और अच्छा कार्य करने वालों को साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी के रूप में सम्मानित भी किया जायेगा। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर पैक्स स्थापित किये जायेंगे। सहकारिता के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिये विभाग के तहत सभी स्तर के विभागीय कार्यालय, सहकारी संस्थाओं में "स्वभावस्वच्छता-संस्कार स्वच्छता" अभियान के तहत स्वच्छता दिवस कार्यक्रम मनाया गया।

नई दिल्ली के इण्डिया हेबिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के तहत सहकारिता क्षेत्र में कुल 2305 करोड़ राशि में 19 एमओयू हुए। यह एक क्रांतिकारी पहल है, जब नये सीपीपीपी मॉडल के तहत इतने एमओयू सहकारिता क्षेत्र में हुए।

विभाग की गतिविधियों पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। सहकारिता विभाग में 25 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी। अब विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। इसी प्रकार अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में आईबीपीएस से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। अपेक्स बैंक में 47 अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है और 197 की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जिला सहकारी बैंकों में 1099 समिति प्रबंधक और 1568 बैंकिंग सहायक की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गयी है और 2675 पदों पर भर्ती की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

मध्यप्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त मॉडल बायलॉज सभी पैक्स में लागू कर पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एम-पैक्स की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में 637 नये एम-पैक्स के गठन की कार्यवाही शुरू है। प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा आमजन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 773 शाखाओं और उनसे संबद्ध 4000 पैक्स संस्थाओं द्वारा लगभग 4800 माइक्रो एटीएम का संचालन किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सरल एवं शीघ्र लेन-देन की बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं।

मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। बीज संघ को उन्नत स्तर पर पहुँचाने का प्रयास जारी है। बीज संघ से चीता बीज के नाम से नया ब्रॉण्ड लांच किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से चीता बीज का वितरण किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मध्यप्रदेश ने भी कैलेण्डर बनाकर सहकारी आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ने और पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति पर भी काम किया जा रहा है। गाँव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 3 शीर्ष स्तर की संस्थाएँ बनायी गयी हैं। इससे सहकारी आंदोलन सशक्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा देश की सभी सहकारी संस्थाओं की जानकारी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल पर अपलोड करायी जा रही है। मध्यप्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं की एन्ट्री पोर्टल पर कर दी गयी है।

मध्यप्रदेश, भारत सरकार की सहकारिता की गतिविधियों में लगातार कदम से कदम मिलाकर सहकारिता आंदोलन को गति देने का काम कर रहा है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश सहकारिता के कई आयामों में अग्रणी होगा।

श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाएं, सरकार खरीदेगी किसानों से श्रीअन्न : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

तुअर उत्पादक किसानों को अच्छे बीज, खाद और उत्पादन वृद्धि के लिए भी दें प्रोत्साहन

सभी मंडियों का विभागीय अधिकारियों से विजिट करायें, प्रबंधन पर दें विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने की किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रागी, कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा, मक्का जैसे श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को श्रीअन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहि त किया जाए। किसानों द्वारा उत्पादित श्रीअन्न अब सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि तुअर उत्पादक किसानों को अच्छे किस्म के खाद, बीज और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाए। इसके लिए किसानों को फसल अनुदान देने और उनकी फसल का बीमा कराने जैसे नवाचार भी किये जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल, सचिव कृषि श्री एम. सेल्वेन्द्रम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि उपज मंडी के अलावा फल व सब्जी मंडी, मसाला मंडी स्थापना के लिए भी करें प्रयास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की सभी मंडियों में प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों का विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से आकस्मिक निरीक्षण करायें। मंडियों की व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई जरूरतों के मुताबिक अब अलग-अलग मंडियों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडियों का फसलवार मॉडल तैयार करें। कृषि उपज मंडी के अलावा अब फल व सब्जी मंडी, मसाला मंडी या अन्य विशेष पैदावार की मंडी स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाएं। इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाए और यदि आवश्यकता है तो इसमें प्रायवेट सेक्टर को भी सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडियों में जारी वर्तमान व्यवस्थाओं का समुचित तरीके से किसानों के हित में प्रबंधन किया जाए। मंडी शुल्क की प्राप्त राशि से किसानों की कल्याण गतिविधियों पर फोकस किया जाए।

आदर्श बनें प्रदेश की कृषि उपज मंडियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को आदर्श बनाया जाए। मंडियों में कृषि आधारित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। मंडियों में किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंडी में अपनी फसल बेचने आने वाले हर किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले किसी का भी नुकसान न होने पाए। मंडियों को और अधिक आधुनिक बनाया जाए यहां किसानों को उनके उपज में गुणवत्ता संवर्धन के बारे में भी बताया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी मंडियां अपने विकास कार्यों के लिए आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्थानीय निकायों से नई मंडियों की स्थापना/ फसल भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए समन्वय करें, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक सुविधाएं मिल सकें।

किसानों को मिले प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रदेश के किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक कृषि यंत्रों, अच्छा भाव, अनुदान आदि का प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि श्रीअन्न रागी, कोदो-कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा की फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए। इन फसलों के उत्पादक क्षेत्र को अच्छी पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। आवश्यकता अनुसार अनुदान की राशि भी बढ़ाई जाए।

ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवारनाशकों के उपयोग को करें हतोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवारनाशकों के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए खरपतवारनाशकों को हतोत्साहित करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिले। स्वाभाविक फसलों की पैदावार पर विशेष जोर दिया जाए।

कृषि उद्योग समागम के अनुभवों से आगे बढ़ें, किसानों को मिले बेहतर परिणाम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर संभाग में किसान मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इन मेलों में कृषि आधारित उद्योगों में निवेश पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में मंदसौर जिले के सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को कृषि के आधुनिक यंत्रों और तकनीक से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीतामऊ में हुए कृषि उद्योग समागम के अनुभवों को सामने रखें और इन अनुभवों के आधार पर आगे होने वाले कृषि उद्योग समागमों की तैयारी करें, जिससे किसानों को इन समागमों से अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि किसानों को खेतों में नरवाई जलाने से रोकने के प्रयास किए जाएं। किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन और हर ग्राम पंचायत में हैप्पी सीडर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

तीन फसलों को जल्द ही मिलेगा जीआई टैग

बैठक में बताया गया कि राज्य शासन की प्रगतिशीलता से प्रदेश में उत्पादित होने वाली 3 फसलों को बहुत जल्द जीआई-टैग मिल जाएगा। सचिव कृषि ने बताया कि डिंडोरी जिले की नागदमन मकुटकी, सिताही कुटकी और बैंगनी अरहर की फसल को जीआई टैग परीक्षण के लिए भेजा गया है, उम्मीद है कि जल्द ही इन फसलों को जीआई टैग प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू करने के बाद प्रदेश में बीते एक अप्रैल 2025 से प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी योजना भी लागू कर दी गई है। सभी मंडियों में अब डिजीटल तरीके से रिकार्ड कीपिंग की जा रही है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के अंतर्गत "एक पेड़ माँ के नाम" विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और मातृशक्ति के सम्मान में हर व्यक्ति द्वारा एक पौधा रोपित करने की प्रेरणा देना है।

इस अभियान के अंतर्गत राज्य सहकारी संघ मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ तीनों सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों –इंदौर, जबलपुर एवं नौगांव – में कुल111 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें से मुख्यालय में 30 तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में 27 पौधे रोपित किए जाएंगे।

05 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवसके अवसर पर पौधारोपण स्थलों पर गड्ढों की खुदाई कर तैयारी की जाएगी,

जिसकी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके बाद05 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवसके उपलक्ष्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

पौधों की नियमित देखभाल हेतु मुख्यालय एवं प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उप प्रबंधक अथवा प्राचार्य करेंगे। साथ ही, पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्र केवन विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

संघ के प्रबंध संचालक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयसीमा में पूर्ण की जाएं एवं गत वर्ष लगाए गए पौधों की स्थिति का विवरण भी संकलित कर भवन कक्ष में संधारित किया जाए।

यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहकारिता विभाग की सहभागिता को दर्शाता है, बल्कि एक भावनात्मक पहल के माध्यम से समाज में मातृ सम्मान का संदेश भी देता है।

कृषि एवं उद्यानिकी में नवाचार और उन्नत तकनीकों से बढ़ाएंगे उत्पादन क्षमता : मुख्यमंत्री

आर्थिक रूप में सम्पन्न हो रहा है मध्यप्रदेश

उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से हो रहे हैं कार्य

किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने सरकार संकल्पित

बिजली में आत्मनिर्भर होंगे किसान : सौर ऊर्जा से बनाएंगे स्वयं बिजली

10 प्रतिशत राशि पर उपलब्ध कराए जाएंगे सोलर पम्प

खेती को लाभदायक बनाने के लिए विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित कर रही है राज्य सरकार

जीवन बेहतर बनाने किसान खेत की एक-एक इंच जमीन को बनाएं उपयोगी

संतरे-केले जैसे प्रदेश के अन्य कृषि उत्पादों की मध्यप्रदेश के नाम पर हो ब्रांडिंग

नरवाई जलाने से बचें किसान : मशीनों से होगा नरवाई का निष्पादन

पीकेसी परियोजना उज्जैन संभाग के किसानों की बदलेगी जिन्दगी

मुख्यमंत्री ने सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम : 2025 को किया संबोधित

किसानों को उन्नत कृषि, बागवानी, फलोद्यान, प्रसंस्करण व अन्य गतिविधियां अपनाते हुए सम्पन्न बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का दिलाया संकल्प

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश, देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। आने वाले समय में प्रगति की गति और तेज होने वाली है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान सौर ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पम्प चलाएंगे। उनके द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। किसानों को मात्र 10 प्रतिशत राशि पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच, तीन, दो हार्स पॉवर तक के सौर पम्प के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। तीन साल में 32 लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान, कृषि पम्प चलाने, घर में बिजली के उपयोग या अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी बिजली स्वयं बना सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीतामऊ (मंदसौर) में कृषि उद्योग समागम : 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदसौर, नीमच क्षेत्र के किसानों द्वारा ली जा रही विविधतापूर्ण उपजों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही सीतामऊ में उन्नत कृषि पर केन्द्रित यह आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कृषि उत्पादों के उचित मूल्य, लंबे समय तक संधारण और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। मध्यप्रदेश में संतरा, केला सहित कई महत्वपूर्ण उत्पाद बड़ी मात्रा में होते हैं। इनकी ब्रांडिंग भी हमारे प्रदेश के नाम पर हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी किसानों को उन्नत कृषि अपनाने और बागवानी, फलोद्यान, प्रसंस्करण सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां अपनाते हुए सम्पन्न बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का संकल्प दिलाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरवाई जलाने की जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। गेहूं की फसल के बाद बचे अवशेष में आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से नरवाई जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के निराकरण के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है और उन पर अनुदान की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ों परियोजना से उज्जैन संभाग के सभी किसानों की जिन्दगी बदलेगी। हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी पहुँचेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गौपालन को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। गौमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक हैं, गाय-भैंस पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 गाय-भैंस पालने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का उत्पादन वर्तमान में 9 प्रतिशत है, इसे हमें 20 प्रतिशत तक ले जाना है। किसानों को 200 गाय-भैंस पालन अर्थात 8 यूनिट तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। दूध-दही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, "जिसके घर गाय वह गोपाल और जिस के घर गाय का कुल वह घर गोकुल" का भाव हमारा परिवेश में रचा-बसा है। अच्छी खेती के साथ दूध उत्पादन, बागवानी, फलोद्यान जैसी गतिविधियां बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपना जीवन उपयोगी बनाने के लिए, किसान खेत की एक-एक इंच जमीन को बेहतर बनाएं। प्रदेश के हर जनपद में एक-एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा, जहां उन्नत कृषि के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ स्कूल-कॉलेज सहित सभी अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बेसहारा, लावारिस, अपाहिज गौमाता की देख-रेख के लिए 20 रूपए के स्थान पर 40 रूपए प्रति गाय की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने आपदा में तत्काल मदद करने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन आरंभ किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाकि विगत दिनों ही गांधी सागर क्षेत्र में चीते छोड़े गए हैं। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय निवासियों को होम-स्टे सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि, बागवानी, उद्योग-धंधों, धार्मिक सहित सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेशवासियों की आय बढ़ाना राज्य सरकार का उद्देश्य है और इस दिशा में प्रतिबद्धतापूर्वक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। महिला, गरीब, युवा और किसान सभी का जीवन बेहतर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम राईज स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण राजस्थान से होते हुए अध्ययन केलिए उज्जैन आए थे, पूरे मार्ग में भगवान श्रीकृष्ण जिस-जिस गांव से गुजरे और जहां-जहां लीलाएं हुईं, उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाएं जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदसौर जिले के लिए 4 सांदीपनि विद्यालय और एक तहसील भवन की स्वीकृति प्रदान की तथा कृषि उद्योग समागम की सभी प्रदर्शनियों की अवधि एक दिन और बढ़ाए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदसौर, नीमच क्षेत्र की समृद्ध पुरातत्व सम्पदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने, बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाने के साथ ही किसान सम्मान निधि देते हुए किसान की मेहनत का सम्मान किया गया है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में और अधिक विस्तार होने जा रहा है।

मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में स्थापित किए नये कीर्तिमान

नरवाई प्रबंधन के लिए 412 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी

भोपाल : मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। साथ ही फसलों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर रिकार्ड बनाया। प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, खाद्यान उत्पादन में द्वितीय स्थान पर एवं तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तृतीय फसली क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। नरवाई जलाने को हतोत्साहित करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाये गये है। कृषकों को फसल आच्छादन के अवशेष जलाने से रोकने के लिये शासन द्वारा कई कदम उठाये गये हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर 46,800 से अधिक नरवाई प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्र अनुदान पर वितरित करते हुए 412 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी की गई है। नरवाई जलाने की घटना वाले कृषकों को आगामी एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार रूपये का भुगतान नहीं किये जाने के साथ ही आगामी एक वर्ष के लिए उनकी उपज का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं करना भी शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है, जिससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। खरीफ 2024 के धान उत्पादक कृषकों को जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। चार हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जायेगा, जिसमें एक कृषक को अधिकतम दस हजार रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदाय की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा रबी 2024-25 में उपार्जित गेहूँ पर 175 रुपए प्रति क्विटंल प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 83.50 लाख से अधिक किसानों को लगभग 1770 करोड़ रुपए उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 24 फरवरी, 2025 को जमा किए गए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 10 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को 1624 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में सिंगल क्लिक से जमा किए गए हैं।

प्रदेश में पहली बार भारत सरकार की सपोर्ट प्राइस स्कीम में सोयाबीन का उपार्जन किया गया, जिसमें 2 लाख 12 हजार 568 कृषकों से 6.22 लाख मीट्रिक मात्रा का उपार्जन किया गया, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि 3043.04 करोड़ रुपए है। श्रीअन्न के उत्पादन को बढावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न (मोटा अनाज) प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसमें किसानों को 3900 रुपए प्रति हैक्टेयर डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में देय होंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का समय पर आंकलन एवं राहत राशि का वितरण किसानों को समय पर मध्यप्रदेश में मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन और दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनसीआईपी पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक एकीकृत करने एवं इस पोर्टल को और अधिक किसान अनुकूल बनाने के लिए 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शासन द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजनांतर्गत प्रदेश में 89 दीदीओं को स्वाबलंबी बनाया गया है। इनके माध्यम से 4200 हैक्टेयर में तरल उर्वरक का छिड़काव तथा राशि रूपये 21.22 लाख की शुद्ध आय प्राप्त की। इस वर्ष 2025-26 में 1066 दीदियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस एवं गेल कंपनी द्वारा स्थापित किये जा रहे सीबीजी प्लांट में फसल अवशेष से कम्प्रेस बायो गैस निर्माण की जायेगी, इसके लिये राज्य सरकार ने नरवाई प्रबंधन से संबंधित हाईटेक हब केन्द्र स्थापना पर हितग्राही को अधिकतम 97.50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदाय किये जाने के लिये विभागीय कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण देश की प्रतिष्ठित निर्माता कंपनी के सहयोग से दिया जाता है। विभागीय केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2024-25 तक 7361 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें से 1939 प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से किसान ड्रोन पायलट प्रशिक्षण एवं ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। कुल 412 युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण तथा 33 प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कृषकों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाये जाने के लिये शासन के जन संकल्प पत्र-2023 के अनुपालन में हर वर्ष 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। पूरे देश में इस योजना की पहल मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2012 में की गई तथा अब तक 4730 कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश स्तर पर स्थापित होकर कृषकों को लाभ दे रहे है। आवेदक को प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10 लाख का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में APEDA अन्तर्गत 11.48 लाख हैक्टयर फसल उत्पादन क्षेत्र एवं वनोपज संग्रहण क्षेत्र सहित 20.55 लाख हेक्टेयर जैविक क्षेत्र पंजीकृत है। "एक जिला-एक उत्पाद" अंतर्गत कृषि संबंधी 06 उत्पाद कोदो-कुटकी-अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल-नरसिंहपुर, चना-दमोह, बासमती चावल-रायसेन, चिन्नोर चावल-बालाघाट, सरसों-भिण्ड एवं मुरैना, अंतर्गत 10 जिले शामिल किये गये है।

फार्म गेट ऐप के तहत किसान अपनी उपज का विवरण, फोटो मोबाइल एप्लिकेशन पर डाल कर मंडी मे पंजीकृत व्यापारियों के साथ मोल भाव कर सकता है। सौदा तय होने पर किसान की सहमति प्राप्त कर व्यापारी सीधे किसान के गाँव या खेत से उपज उठा लेता है। इससे भौतिक रूप से माल के परिवहन की आवश्यकता नहीं रहती। यह उपज न बिकने की अनिश्चितता को समाप्त करता है। मंडी में सही दाम न मिलने पर भी, विशेषकर छोटे और मध्यम किसान जिनके पास अपने परिवहन के साधन नहीं होते है, उन्हें अब मजबूरी में उपज नहीं बेचना पड़ती है। भाड़े की बचत होती है। मंडी के माध्यम से किसान को मंडी अनुबंधित व्यापारी का चयन कर खेत या गोदाम पर ही फसल को बेचने की सुविधा है।

मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध : डॉ. यादव

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापारी और निवेशक मध्यप्रदेश आएं और उद्योग को बढ़ावा दें। आज मेड इन इंडिया का जमाना है। मध्यप्रदेश सरकार ने नई उद्योग केंद्रित नीतियां लागू की हैं। सभी जिलों में उद्योग प्रकोष्ठ खोले गए हैं। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। निवेशकों के लिये मुख्यमंत्री सहजता से उपलब्ध है। राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक, पानी और बिजली उपलब्ध है। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक-एक रुपया लौटाया है। सरकार बड़े उद्योगों के साथ छोटे निवेशकों को भी प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को बेंगलुरू में हुए रोड-शो के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। इंटरेक्टिव सेशन में विभिन्न निवेशकों से चर्चा हुई। आज निवेशकों से 7935 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 18 हजार 975 नए रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म" के मूल मंत्र को आधार बनाकर हम आत्म-निर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापनाऔर निवेश को बढ़ावा देने क`लिये हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय पर विभिन्न शहरों में किये गये रोड-शो और इंटरेक्टिव सेशन सहित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से हमने लोकल से ग्लोबल स्तर तक सफलतापूर्वक निवेश संवाद किया है। बेंगलुरु में आज दूसरी बार हुए रोड-शो और इंटरेक्टिव सेशन से निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए "प्रगतिशील, पारदर्शी और भरोसेमंद राज्य"केरूपमेंउभराहै।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारा शेयर बाजार नई ऊँचाईयों को छू रहा है। निवेशक मध्यप्रदेश आएं और अपने उद्योग को बढ़ाएं। एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, वहीं का होकर रह जाता है। सभी प्रकार के उद्योगों के विकास का कार्य मध्यप्रदेश में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश केवल निवेश का वादा नहीं करता, हम जिनसे कमेटमेंट करते है, उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा भी कर रहे है। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025 में हमने केवल वादे नहीं किए, उन्हें धरातल पर भी उतारा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 5260 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि बड़े उद्योगों और एमएसएमई को वितरित की गई है। प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में निवेश संवर्द्धन के लिये 18 नई औद्योगिक नीतियां लांच की गई, जो आज निवेश के लिये गेम चेंजर साबित हो रही हैं। जनविश्वास अधिनियम, एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विकसित किये जा रहे पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क (धार), नर्मदापुरम मेन्युफैक्चरिंग ज़ोन, रीवा, इंदौर एवं उज्जैन मे नई आईटी परियोजनाओं, उज्जैन में 5 जून 2025 को 'स्पिरिच्युअल एवं वेलनेस समिट' एवं अन्य क्षेत्र जैसे फार्मा, माइनिंग, कृषि, डेयरी, नवकरणीय ऊर्जा आदि संभावनाओं के बारे मे निवेशकों को अवगत कराया जा रहा है। निवेश को आकर्षित करने, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिये 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025' अंतर्गत आज बेंगलुरु में हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के साथ भूमि आवंटन और 'इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश' विषय पर सफल इंटरेक्टिव सेशन किया।

मत्स्य प्रबंधन की दिशा में समन्वय की पहल - उड़ीसा राज्य के अधिकारियों का मध्यप्रदेश में अध्ययन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न

भोपाल, मत्स्य प्रबंधन एवं सहकारिता के क्षेत्र में परस्पर अनुभवों के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करते हुए उड़ीसा राज्य मत्स्य विभाग के 13 वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि दल दिनांक 1 मई से 6 मई 2025 तक मध्यप्रदेश के विभिन्न जलाशयों, संस्थानों और योजनाओं का शैक्षणिक एवं तकनीकी अध्ययन भ्रमण हेतु आगमन पर रहा। यह भ्रमण न केवल राज्यों के बीच सहयोग का सेतु बना, बल्कि मत्स्य पालन की सतत और समावेशी रणनीतियों की दिशा में एक उपयोगी संवाद भी सिद्ध हुआ। दल ने दिनांक 4 मई 2025 को भोपाल स्थित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के छात्रावास में विश्राम किया।

मत्स्य महासंघ में संवाद और जानकारी का आदान-प्रदान

5 मई 2025 को अध्ययन दल ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल का भ्रमण किया। महासंघ की प्रबंध संचालक, श्रीमती निधि निवेदिता, आई.ए.एस.ने अधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने दोनों राज्यों में मत्स्य पालन की नीतियों, नवाचारों और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए आपसी सहयोग के नए क्षितिजों की संभावना व्यक्त की।

महासंघ के महाप्रबंधक श्री बी.आर. राय द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से राज्य में क्रियान्वित योजनाओं, वित्तीय मॉडल, मत्स्य संसाधनों की प्रबंधन प्रणाली एवं सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

प्रभारी रीजनल मैनेजर श्री आरिफ अंसारी ने महासंघ द्वारा संचालित 28 डेमो जलाशयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों - मत्स्य पालन, मत्स्याखेट, विपणन एवं सहकारी समितियों को राज्य शासन द्वारा प्रदत्त 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की जानकारी साझा की। दल को बताया गया कि किस प्रकार उत्पादन और विपणन की संगठित प्रणाली ने मत्स्य पालकों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।

प्रतिनिधि दल ने इस प्रक्रिया में रुचि

दिखाते हुए अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान संबंधित अधिकारियों ने विस्तार से किया। यह संवाद अनुभवों की साझेदारी से परिपूर्ण रहा, जिसने मत्स्य नीति के क्षेत्र में नवाचार को नया दृष्टिकोण प्रदान किया।

राज्य सहकारी संघ में शिष्टाचार भेंट एवं सहकारिता के अनुभव

भ्रमण के अंतिम दिन6 मई 2025 को, अध्ययन दल ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के सभा कक्ष में संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर परसंघ के उप प्रबंधक श्री गणेश प्रसाद मांझी, पूर्व प्राचार्य श्री ए.के. जोशी एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान भी उपस्थित रहीं।

प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारासंघ में संचालित प्रशिक्षण, प्रकाशन, नीति निर्माण, महिला सहभागिता, युवा समावेशन जैसी विविध गतिविधियों की जानकारी दी गई। दल कोसंघ के ब्रॉशर, सहकारी नीति दस्तावेज एवं 'मध्यप्रदेश सहकारी समाचार' की प्रतियाँ भेंट की गईं, जिससे उन्हें संस्थागत क्रिया-कलापों की समग्र जानकारी प्राप्त हुई।

प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की जानकारी एक प्रभावशाली स्लाइड प्रजेंटेशन के माध्यम से दी। इससे सहकारी संस्थानों में अन्य मंत्रालयों की समन्वित भागीदारी को भी बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला।

इस सफल आयोजन में श्रीमती सुमना दत्ताका विशेष योगदान रहा। उन्होंने मत्स्य महासंघ में कार्यक्रम संचालन और आगंतुकों के स्वागत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संवाद, सहयोग और समर्पण का सेतु

यह अध्ययन भ्रमण केवल एक शैक्षणिक यात्रा नहीं था, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ाया गया वह हाथ था, जिसमें सहयोग, समझ और सतत विकास की आकांक्षा समाहित थी। उड़ीसा राज्य के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश सरकार एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यों की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए भविष्य में आपसी सहयोग की संभावनाओं को और मजबूत बनाने की अभिलाषा व्यक्त की।

यह भ्रमण निश्चित रूप से भारत के सहकारी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतराज्यीय समन्वय की दिशा में एक अनुकरणीय पहल के रूप में याद किया जाएगा।

जागृति कामकाजी महिला सहकारी संस्था का आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा सहकारी प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 27 मई 2025 को साख सहकारी समिति – जागृति कामकाजी महिला सहकारी संस्था, भोपालमें एक दिवसीयआधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमका आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सदस्यों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सहकारिता के मूल सिद्धांतों, संचालन प्रक्रियाओं तथा डिजिटल युग में सहकारिता के प्रभावी उपयोग की जानकारी प्रदान करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख झलकियाँ

कार्यक्रम का शुभारंभ समिति की अध्यक्ष श्रीमती रीतू गुर्जर एवं संयोजकश्रीमती सुमति तिग्गाद्वारा मुख्य वक्ताओं को पौधा भेंट कर स्वागत एवं सम्मान के साथ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संस्था की सजगता को भी दर्शाता है।

1. सहकारिता का इतिहास एवं संरचना पर व्याख्यान

श्री गणेश प्रसाद मांझी, उप प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ, भोपाल ने

प्रतिभागियों को सहकारिता आंदोलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसकी आवश्यकता, उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा संगठनात्मक संरचना की जानकारी दी। उन्होंने आमसभा, संचालक मंडल की बैठकें एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया।

2. वित्तीय लेखांकन एवं अंकेक्षण

श्रीमती रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी ने साख सहकारी समितियों में लेखांकन की प्रक्रिया, वार्षिक बजट, बहीखाता संधारण एवं अंकेक्षण के मानकों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने व्यावसायिक पारदर्शिता और लेखा उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया।

3. डिजिटल सहकारिता एवं विभागीय पोर्टल

संघ की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बानने सहकारिता विभाग के पोर्टल एवं वेबसाइट के उपयोग, सूचनाओं की उपलब्धता, ऑनलाईन पंजीयन, बैठक अपलोडिंग एवं डेटा प्रबंधन जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल प्रबंधन को समय की आवश्यकता बताया।

4. सोशल मीडिया और प्रचार-प्रसार

श्री योगेश नामदेव एवं श्री रोबिन सक्सेना, डोमेन एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहकारी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार, ब्रांडिंग, जनजागरूकता तथा संवाद-संचार की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रभावी उपयोग से संस्था की पहुँच और साख में वृद्धि की जा सकती है।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और आग्रह

प्रशिक्षण सत्र के समापन पर प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। उन्होंने माना कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से संस्था के सदस्यों की क्षमता विकास, कार्यकुशलता एवं जागरूकता में वृद्धि होती है। प्रतिभागियों ने अनुरोध किया कि ऐसे प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किए जाते रहें ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

आभार एवं समापन

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में संस्था की अध्यक्ष श्रीमती रीतू गुर्जर ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल से पधारे सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण शाख सहकारी समिति की मजबूती, पारदर्शिता एवं जनहितकारी गतिविधियों के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।